

1. भारत और अमेरिका ने सीबीसी रिपोर्ट एक दुसरे के साथ साझा करने का समझौता हुआ

इस समझौता का मुख्य उद्देश्य सीमा पार कर चोरी पर अंकुश लगाना है। इस समझौते के साथ द्विपक्षीय सक्षम प्राधिकरण की व्यवस्था भी भारत-अमेरिका के बीच लागू हो जाएगी।

भारत और अमेरिका के बीच 27 मार्च 2019 को एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के तहत दोनों राष्ट्र देश-दर-देश (सीबीसी) रिपोर्ट का आदान-प्रदान करेंगे। यह एक अंतर-सरकारी समझौता है। इसका प्रत्यक्ष लाभ दोनों देशों में मौजूद बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मिलेगा। इस समझौता का मुख्य उद्देश्य सीमा पार कर चोरी पर अंकुश लगाना है। इस समझौते के साथ द्विपक्षीय सक्षम प्राधिकरण की व्यवस्था भी भारत-अमेरिका के बीच लागू हो जाएगी। इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच ऑटोमैटिक तरीके से सीबीसी रिपोर्ट का आदान-प्रदान आसान हो जाएगा। समझौते पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन पी. सी. मोदी और भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ आई. जस्टर ने हस्ताक्षर किए।

सीबीसी रिपोर्ट क्या होती है?

सीबीसी रिपोर्ट में किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी की देश-दर-देश सूचना होती है। सीबीसी रिपोर्ट में किसी भी एमएनई समूह की आय के वैश्विक आवंटन, अदा किए गए करों और कुछ अन्य संकेतकों से संबंधित देश-दर-देश सूचनाओं का संकलन किया गया है। इसमें किसी विशेष क्षेत्राधिकार में कार्यरत एमएनई समूह के सभी घटक निकायों की सूची है और इसके साथ ही इस तरह के प्रत्येक घटक निकाय के मुख्य कारोबार के स्वरूप का भी उल्लेख किया गया है। किसी एक वर्ष में 750 मिलियन यूरो (अथवा कोई समतुल्य स्थानीय मुद्रा) अथवा उससे अधिक का वैश्विक समेकित राजस्व अर्जित करने वाले एमएनई समूहों के लिए अपने जनक निकाय के क्षेत्राधिकार में सीबीसी रिपोर्टों को दाखिल करना आवश्यक है। भारतीय मुद्रा रुपये में 750 मिलियन यूरो की समतुल्य राशि को भारतीय नियमों के तहत 5500 करोड़ रुपये के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। दोनों ही कर प्रशासनों द्वारा इस सूचना की बदौलत टैक्स संबंधी जोखिम का बेहतर आकलन करना संभव हो पाएगा।

अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में जानकारियाँ

FATF:- [अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें](#)

OIC:- [इस्लामी सहयोग संगठन Organisation of Islamic Cooperation-](#)

उद्देश्य

- ✓ 1972 में अपनाये गये चार्टर के आधार पर ओआईसी के उद्देश्य हैं- सदस्य देशों के मध्य आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस्लामी एकजुटता को प्रोत्साहन देना तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों से जुड़े सदस्यों के मध्य परामर्श की व्यवस्था करना;
- ✓ किसी भी रूप में विद्यमान उपनिवेशवाद की समाप्ति तथा जातीय अलगाव और भेदभाव की समाप्ति के लिये प्रयास करना;

- ✓ न्याय पर आधारित अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विकास के लिये आवश्यक कदम उठाना; धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के प्रयासों में समन्वय स्थापित करना फिलिस्तीन संघर्ष को समर्थन तथा उनके अधिकारों और जमीनों को वापसी में उन्हें सहायता देना;
- ✓ विश्व के सभी मुसलमानों की गरिमा, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करने के लिये उनके संघर्षों को मजबूती प्रदान करना, तथा; सदस्य देशों और अन्य देशों
- ✓ के मध्य सहयोग और तालमेल को प्रोत्साहित करने के लिये एक उपयुक्त वातावरण तैयार करना।

UN:- United Nations एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश हैं, विश्व के लगभग सारे अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त देश। United Nations की 6 अंग हैं- महा सभा, सुरक्षा परिषद, (मसूदा अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव) आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (कुलभूषण यादव का मामला), न्यायसिद्ध परिषद सम्मिलित है।

भारत की आन्तरिक सुरक्षा ब्यस्था:- [जानने के लिए क्लिक करें](#)

UNO:- United Nations Organisation: [जानने के लिए क्लिक करें](#)

MFN रास्ट्रीय

किसी भी कारण से चर्चा में आए महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं स्थान

विंग कमांडर अभिनन्दन

कुलभूषण यादव